भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1442

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा प्रीमियम में वृद्धि

1442. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीएसटी सुधारों के तहत व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को घटाकर शून्य करने के बावजूद, राजस्थान सहित कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने मूल प्रीमियम को 8 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बीमा कंपनियों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ताकि जीएसटी सुधारों का लाभ नए पालिसीधारकों को मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो इसे लागू करने की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सूचित किया है कि दर में कटौती के पूर्ण संचरण सुनिश्चित करने के लिए, 17 सितंबर, 2025 को बीमा कंपनियों के साथ एक दिवसीय व्यक्तिगत तौर पर वार्ता आयोजित की गई थी। पॉलिसीधारकों को अक्षरश: पूर्ण लाभ देने की आवश्यकता पर उन्हें बल दिया गया। इसके अलावा, आईआरडीएआई ने 3 सितंबर, 2025 तक प्रचलित प्रीमियम दरों को एकत्र किया है और नई पॉलिसियों के साथ-साथ पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए नियमित रूप से प्रीमियम की निगरानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमित व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो।

इस संबंध में, आईआरडीएआई ने सूचित किया है कि जनवरी, 2026 में सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से एक पुष्टि हुई है कि उन्होंने सरकार की जीएसटी राहत की घोषणा के बाद प्रीमियम को संशोधित नहीं किया है। उन्होंने आगे पुष्टि की है कि सरकार द्वारा दी गई जीएसटी राहत पूरी तरह से पॉलिसीधारकों को दे दी गई है।

आईआरडीएआई ने यह भी सूचित किया है कि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, पॉलिसी की अवधि के दौरान योजना के तहत उपलब्ध प्रीमियम और लाभों को बदला नहीं जा सकता है।

*****